

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1574
उत्तर देने की तारीख - 09/02/2026

पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

1574. श्री संतोष पांडेय:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 2025 तक प्रधानमंत्री श्री योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को जिला-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को सुदृढ़ करना है, जिनमें से केविस/नविस/एनसीईआरटी के साथ-साथ 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार 13,076 स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूलों के रूप में किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविस/नविस/एनसीईआरटी-वार संख्या **अनुलग्नक-I** के रूप में दी गई है।

(ख): पीएम श्री योजना के तहत, कुल 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और केवल 2 राज्यों को अभी तक एमओयू पर हस्ताक्षर करना है जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/तारीख-वार सूची जिस पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। पीएम श्री योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कूल स्तर पर कमी की पहचान करके प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत घटकवार प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वित्तीय और कार्यक्रम मानदंडों और उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा स्वीकृत किया जाता है। विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधि समग्र रूप से जारी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला-वार और स्कूल-वार आवंटन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को पीएम श्री योजना के तहत आवंटित निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	अनुमोदित पीएबी परिव्यय	अनुमोदित पीएबी परिव्यय का केंद्रीय हिस्सा
2023-24	65.79	39.47
2024-25	201.41	120.85
2025-26	196.78	118.07

नोट- परिव्यय निधि में प्रतिबद्ध देयता शामिल है।

अनुलग्नक-I

पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संतोष पांडेय द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1574 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम श्री योजना के अंतर्गत चुने गए स्कूलों की राज्य/संघ राज्य/केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य /केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी	पीएम श्री स्कूलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16
2	आंध्र प्रदेश	935
3	अरुणाचल प्रदेश	93
4	असम	382
5	बिहार	836
6	चंडीगढ़	2
7	छत्तीसगढ़	341
8	दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव	7
9	दिल्ली	6
10	गोवा	28
11	गुजरात	463
12	हिमाचल प्रदेश	199
13	हरियाणा	250
14	जम्मू और कश्मीर	396
15	झारखंड	363
16	कर्नाटक	585
17	लद्दाख	37
18	लक्षद्वीप	11
19	मध्य प्रदेश	799
20	महाराष्ट्र	860
21	मणिपुर	121
22	मेघालय	65
23	मिजोरम	35
24	नगालैंड	49
25	ओडिशा	762
26	पुदुचेरी	12
27	पंजाब	356
28	राजस्थान	639
29	सिक्किम	47
30	तेलंगाना	794
31	त्रिपुरा	84
32	उत्तराखंड	241
33	उत्तर प्रदेश	1725
34	केवीएस	913
35	एनवीएस	620
36	एनसीईआरटी	4
	कुल	13076

अनुलग्नक-II

पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संतोष पांडेय द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1574 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/तिथवार सूची इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि
1	महाराष्ट्र	06-10-2022
2	हरियाणा	06-10-2022
3	कर्नाटक	12-10-2022
4	जम्मू और कश्मीर	13-10-2022
5	मध्य प्रदेश	13-10-2022
6	राजस्थान	14-10-2022
7	गुजरात	14-10-2022
8	मेघालय	14-10-2022
9	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	14-10-2022
10	चंडीगढ़	14-10-2022
11	असम	14-10-2022
12	आंध्र प्रदेश	17-10-2022
13	उत्तर प्रदेश	19-10-2022
14	त्रिपुरा	20-10-2022
15	अरुणाचल प्रदेश	25-10-2022
16	पुदुचेरी	28-10-2022
17	पंजाब	28-10-2022
18	उत्तराखंड	28-10-2022
19	लद्दाख	01-11-2022
20	मणिपुर	04-11-2022
21	छत्तीसगढ़	04-11-2022
22	गोवा	04-11-2022
23	मिजोरम	11-11-2022
24	सिक्किम	11-11-2022
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14-11-2022
26	लक्षद्वीप	17-11-2022
27	नगालैंड	21-11-2022
28	तेलंगाना	15-12-2022
29	हिमाचल प्रदेश	04-03-2023
30	झारखंड	30-06-2023
31	बिहार	04-03-2024
32	ओडिशा	09-07-2024
33	दिल्ली	22-10-2024
34	केरल	23-10-2025
